**REFERENCE TO THE WIDESPREAD EXPLOITATION OF SMALL AND MARGINAL FARMERS IN BIHAR**

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव** (बिहार) : सभापति महोदय, मेरा स्पेशल मेंशन था, इसलिये मैंने वाक आउट नहीं किया, नहीं तो मुझे भी उनके साथ जाना चाहिये था। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और मैं अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस विषय को उठाने का समय दिया। 1982 से मैं एक न्याय के लिये लड़ रहा हूं और वित्त विभाग मे इसकी जांच पड़ताल भी कराई गयी। ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी जांच पड़ताल करायी और सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है कि बिहार में जो पंपिग सैट के बोरिंग के पाइप 9 गेज के किसानों को मिलने थे, वे 11 गेज के और 13 गेज के दिये गये और 18 रुपये के पाइप को बैंकों ने 26 रुपये में किसानों को दिया। 4500 का जो पंपिग सेट था, वह किसानों को 5500 और 6500 में दिया गया और स्ट्रेनर जो 185 रुपये का था, वह उन को 260 रुपए में दिया गया। यह बात मैं ही नहीं कहता बल्कि सदन में इस को सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। सरकार ने यह भी कहा कि सेन्ट्रल बैंक के 6 अधिकारियों और 9 व्यापारियों के खिलाफ सी० बी० आई० ने मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया है। लेकिन मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जो बिहार का लैंड मार्टगेज बैंक है सरकार ने स्वीकार किया था कि लैंड मार्टगेज बैंक में सब से ज्यादा धांधली हुई है और 4500 का पम्पिग सेट 6500 का देने के बाद भी उस के किसी अधिकारी या उसके चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। किसानों का जो करोड़ों रुपया लूट लिया गया, वित्त मंत्री मान रहे हैं, सरकार मान रही है और दोषी अधिकारियों पर मुकदमा आप नहीं चला रहे है, दूसरी तरफ किसान से जो ज्यादा लूटा गया, उसको वापस नहीं कर रहे हैं। किसान का सूद माफ नहीं कर रहे हैं। बोरिंग पम्प सैट पर 5 हजार रुपया किसानों से ज्यादा लूट लिया गया है, जब आपने यह मान लिया है, तो उसको वापस कर दीजिये। सूद माफ नहीं किया गया है, तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो लैण्ड मार्टगेज बैंक हैं, बिहार का, वह सबसे ज्यादा लूट लिया है। उसके चेयरमैन, उसके अधिकारियों पर आयोग बैठाइये। मुकदमा चलाइये, जिस तरह से सेंट्रल बैंक के अधिकारियों के खिलाफ आपने चलाया। उसी तरह से इन बैंकों के अधिकारियों को पकड़िये और किसान को उसका पैसा वापस दिलवाइये, जिससे करोड़ों किसानों को लाभ हो। सभापति महोदय, कोई न कोई रास्ता सरकार को निकालना चाहिये, नहीं तो वहां भयंकर स्थिति पैदा होगी। किसानों की जमीन, उनके खेत, उनके मकान नीलाम हो जायेंगे।

**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, मैं पूर्णतया सहमत हूं, श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी ने जो विचार प्रकट किये हैं, उनसे।

---

**REFERENCE TO THE CLOSURE OF TAMIL EDITION OF "UNESCO COURIER".**

*SHRI VALAMPURI JOHN* (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the Government to the impending closure to UNESCO Courier, a monthly Indian edition in Tamil. Since 1967 this publication faces closure because of the unhelpful attitude of the Department of Human Resource Development.

During the forty years UNESCO has been promoting international peace and understanding through its publications, especially the UNESCO Courier, which is published today in 32 languages of the world. This monthly has been published in Tamil for the past 18 years. The Hindi and Tamil issues of the UNESCO Courier are rendering great intellectual service in India.

The unique feature of the Tamil UNESCO Couriesr is that it is the only Tamil monthly devoted for a subject of

international interest and it reaches Tamil scholars and students throughout the world wherever Tamil as a language is understood and its rich literature is appreciated. The publication of UNESCO Courier in Tamil is a great service to the cause of Tamil language, especially in the field of translation. Each issue of the Tamil Courier bears ample evidence to the fact that all ideas in science and technology can be translated into Indian languages in general and Tamil in particular in easily understandable style. The addition of new technical terms in various branches of knowledge really enriches Tamil language and is of great use to other scholars and institutions that are engaged in translation. UNESCO has applauded on a number of occasions the Tamil Edition of UNESCO Courier and its editor Mr. Mustafa since it renders a signal service to Tamil language and literature. On the other hand the Hindi counterpart has been chastised by the UNESCO since its publication has been irregular and erratic. While this Tamil edition is mainly backed by the Finances of UNESCO and Government of Tamil Nadu, the Ministry of Human Resource Development has been sanctioning only Rs. 2 lakhs in a year for this useful fruitful literary persuit and cultural endeavour.

[**The Deputy Chairman** in the Chair].

After 18 years of uninterrupted publication, at a time when the Government of Tamil Nadu has placed an order for 10,000 copes for its various institutions, the Government of India has not cleared publication for the year 1986 till date. This is happening for the first time in the last 18 years since the inception of the monthly. If the Tamil Edition of UNESCO Courier ceases publication due to the non-cooperation of the Union Government, there would be widespread resentment in Tamil Nadu.

The Government of India may look into this inordinate delay and immediately chastise those officers responsible for this. UNESCO Courier Tamil Edition has been taking not only Tamil ethos but the composite culture of India throughout the world. Therefore, I would like to request the hon. Minister to see that this useful, indispensable journal is continued.

## REFERENCE TO THE EXCESSIVE USE OF FORCE BY POLICE IN DELHI ON 19TH DECEMBER, 1985, AGAINST PEACEFUL MARCHERS FROM HARYANA

**श्री सुशील चन्द्र मोहन्ता** (हरियाणा) : महोदया, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि 10 लाख से भी अधिक आदमी, किसान और मजदूर हरियाणा से पैदल यात्रा करके न्याय की खोज के लिये दिल्ली पहुंचे, रामलीला ग्राउंड में और वहां से शांतिपूर्वक पैदल चलते हुये इंडिया गेट पर आये अपना रोष प्रकट करने के लिये कि हरियाणा के साथ भेदभाव बहुत बरता जा रहा है। जहां उसे रकबा मिलना चाहिये था, फाजिल्का का इलाका उसको दिया नहीं गया, चंडीगढ़ उससे ले लिया गया, चंडीगढ़ के बदले राजधानी देने और नया कैपिटल बनाने के लिये कोई निर्णय नहीं किया गया है, कितना हमको लोन दिया जायगा, कितनी राशि दी जायेगी, इसका पता नहीं। इसके लिये रोष प्रकट करने के लिये वे इंडिया गेट पर आये। लेकिन पुलिस ने नाजायज तौर पर पैनिकी होकर, घबराकर बिला वजह उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। अश्रुगैस छोड़ी गई और इतनी ज्यादा तादाद में छोड़ी गई कि जो इंडिया गेट पर लोग खड़े थे उन लोगों की भी आंखें जलने लगी थी। वे आये थे यहां पर न्याय मांगने के लिये और बरसाई गई उन पर लाठियां, अश्रुगैस उन पर छोड़ी गई। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप स्पष्ट तौर से खड़े हो कर यह बयान क्यों नहीं देते हैं कि आपका हरियाणा के कलेम के बारे में यह विचार है। हम कितने जोर-जोर से यह आवाज उठा रहे हैं। हमने हर गांव में जलसे किये, डिस्ट्रिक्ट लैबल पर जलसे किये, प्रांतीय लैबल पर जलसे किये, इतना बड़ा मुजाहिरा, इतनी बड़ी ताकत यहां पर आपको दिखाई लेकिन आपकी ओर से एक लफ्ज भी नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल चुप्पी साधे हुये हैं। बोल नहीं रहे हैं। हमें इस बात का भारी दुख है। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि हरियाणा के साथ भेदभाव की नीति छोड़ दीजिये। अगर आप यह नीति